S. No. Journal No.
UGC List 20236 41241

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
website : www.pramanaresearchjournal.com
Impact Factor : 6.201

यतेमहि स्वराज्ये
ISSN : 2249-2976

Pramāna

Research Journal

(Art, Literature, Humanity, Social Science, Commerce, Management, Law & Science Subjects)

(Indexed & Listed at :

Research Bib., Japan
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

(An International Peer Reviewed and Refered Research Journal)

Year : 10
Issue : 40
Apr-Jun 2022
www.pramanaresearchjournal.com

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

Acharya Academy, Bharat

ISO : 9001-2015

Principal
Dayanand College
HISAR

शोध–आलेखानुक्रम

- सम्पादकीय
  –आचार्य शीलक राम
- Analytics of Banking Patterns in Indian Scenario
  Dr. Manjeet — *8-12*
- शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा नैराश्य प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन
  डॉ. गीता रावत शाह, डॉ. बी.सी. शाह — *13-19*
- आधुनिक समय में कर्मयोग की उपादेयता
  दानिस फातमा, प्रो. एस. बी. नाथ श्रीवास्तव — *20-22*
- कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी 'मान भी जा साँझी' में नारी की आर्थिक समस्याएं
  सीमा देवी — *23-27*
- दक्षिण एशिया में चीन की रणनीति एवं चुनौतियाँ
  डॉ. रविन्द्र कुमार — *28-34*
- द्विवेदी युगीन कवयित्रियां–जीवन वृत्त रचनाएं, काव्य प्रवृत्तियाँ एवं काव्य विषय
  डॉ. गीता खोलिया — *35-40*
- महाकवि कालिदास, के साहित्य में नायिका–शकुन्तला
  डॉ. सुमन रघुवंशी — *41-44*
- 21वीं सदी में छात्रों के विकास में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन
  डॉ. अनीता सिंह, शिवनन्दन शर्मा — *45-47*
- महामहोपाध्याय मथुरा प्रसाद दीक्षित का स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान
  डॉ. शीशराम — *48-51*
- Matrix Operations and Usage Patterns in Dynamic Applications
  Sanchita — *52-55*
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में एक अध्ययन
  रुचि शर्मा, प्रो. सत्यवीर सिंह — *56-60*
- आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वाधीन राष्ट्रवादी चेतना की अभिव्यक्ति
  प्रियंका गोंड — *61-65*
- Distressed Married Life: A Study of Anita Desai's *Cry, the Peacock*
  Dr. Satpal Singh, Dr. Kavita Sharma — *66-69*
- ''पुराणों एवं परम्पराओं में इतिहास दर्शन का बोध और इतिहास की धार्मिक अवधारणा''
  डॉ. शैलेन्द्र कुमार — *70-72*
- आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता
  रीतु — *73-76*
- Key Dimensions and Scope with Particle Physics
  Anjali — *77-79*
- Human Resource Management and Impact on Performance in Organization
  Dr. Asha — *80-84*

Principal
Dayanand College
HISAR

Pramāna
International Refereed
& Peer Reviewed
Impact Factor : 6.201
Research Journal (ISSN : 2249-2976)
Year-10, Issue-40 (Apr.-Jun 2022) (Page No. 28-34)

दक्षिण एशिया में चीन की रणनीति एवं चुनौतियाँ

डॉ. रविन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा अध्ययन विभाग
दयानन्द महाविद्यालय, हिसार
(हरियाणा)

शोध आलेख सार

दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र आपस में जुड़े हुए हैं फिर भी यहाँ क्षेत्रीय एकीकरण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र एक लम्बे समय से विभिन्न प्रकार के संघर्षों तथा विवादों से ग्रसित हैं। भारत ने दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सदैव मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया है, लेकिन विड़म्बना यह है कि उसे सदैव इन राष्ट्रों से चुनौती मिलती रही है। वर्तमान वस्तुस्थिति यह है कि दक्षिण एशिया के इन राष्ट्रों में घरेलू मोर्चे एवं आपसी टकराव की कई परिस्थितियाँ बनी हुई है। जिसका फायदा उठाकर अमेरिका तथा चीन जैसी बड़ी विश्व शक्तियों ने दक्षिण एशियाई भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अपनी प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है। चीन अपनी रणनीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक तथा सैनिक सहायता देकर भारत की दक्षिण एशिया में जल व थल में भारत की घेराबंदी करना चाहता है।

मुख्य शब्द : दक्षेस, भारतीय उपमहाद्वीप, लोकतन्त्र, राजतन्त्र।

दक्षिण एशिया का परिचय

दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है जिसका प्रयोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है। सामान्यत: इस शब्द से आशय हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों से होता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को दक्षिण एशिया के देश या भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहा जाता है जिसमें नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लिया जाता है। दक्षिण एशिया में आठ देश अवस्थित हैं। दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन दक्षेस भी है जिसके सदस्य देश निम्नवत हैं। जैसे - भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आपस में जुड़े हुए है फिर भी यहाँ क्षेत्रीय एकीकरण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र एक लम्बे समय से विभिन्न प्रकार के संघर्षों तथा विवादों से ग्रसित है। भारत ने दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सदैव मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया है, लेकिन विड़म्बना यह है कि उसे सदैव इन राष्ट्रों से चुनौती मिलती रही है, क्योंकि भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका इत्यादि इस बात के लिए आशंकित रहते है कि भारत उस पर अपना वर्चस्व न बना ले। इसलिए अमेरिका तथा चीन जैसी बड़ी शक्तियों ने दक्षिण एशियाई रणनीति में भारतीय उपमहाद्वीप की सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। जिससे समस्त दक्षिण एशिया प्रभावित हुआ है। जिसका फायदा उठाकर चीन दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति तथा चुनौतियाँ विकसित कर

Principal
Dayanand College
HISAR

रहा है ताकि दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव को कम किया जा सके, जो भारत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध और चीन की रणनीति

भारत तथा पाकिस्तान बंटवारे से पहले एक राष्ट्र था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हिन्दू तथा मुसलमानों के झगड़े के कारण यह 14 अगस्त 1947 में यह दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभक्त हो गया था क्योंकि पाकिस्तान का जन्म भारत के विरोध स्वरूप साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के राजनेता एवं धार्मिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए निरन्तर भारत का विरोध करते है। चीन भारत का पड़ोसी एवं परम्परागत शत्रु राष्ट्र है, इसलिए वह भी पाकिस्तान को सैनिक व अन्य सहायता उपलब्ध कराता है ताकि पाकिस्तान का झुकाव भारत के बजाय चीन की ओर बना रहे।[1]

इसलिए चीन ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय भारत के प्रति शत्रुता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया और सैनिक साजो-सामान से भी सहायता की। परन्तु चीन ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया।[2]

संयुक्त राज्य अमेरिका को भी विश्वास था कि चीन हस्तक्षेप करेगा परन्तु भारत-सोवियत संघ मैत्री संधि 1971 की पृष्ठभूमि में न तो चीन ने हस्तक्षेप की और न ही अमेरिका ने। हस्तक्षेप को छोड़ शेष सभी प्रकार से चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि ने तो भारत के दशष्टिकोण को 'गुण्डागर्दी का तर्क' तक कह डाला।[3]

पाकिस्तान एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

चीन व पाकिस्तान के मध्य निरन्तर सुदृढ़ हो रहे नाभिकीय व सामरिक सम्बन्ध 21वीं शताब्दी में भारतीय सुरक्षा के लिए विराट चुनौती है, क्योंकि चीन भारत को दक्षिण एशिया में ही उलझाए रखना चाहता है। पाक अधिकश्त कश्मीर में चीन की बढ़ रही सामरिक गतिविधियाँ भारतीय सुरक्षा के लिए कदापि शुभ नहीं है, क्योंकि अब भारत को चीन व पाक के साथ दो मोर्चों पर सामरिक मुठभेड़ हेतु विवश होना पड़ सकता है। स्थलीय युद्ध अध्ययन के भारतीय सेना सेंटर के निर्देशक ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल ने यह आशंका प्रकट की है कि-''भविष्य में भारत को पर्वतीय क्षेत्रों में चीन व पाक के पश्थक अथवा संयुक्त आक्रमण का सामना करने की प्रबल आशंका है।'' चीन भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत को अशांत करने में निरंतर लगा हुआ है।

इसके लिए चीन पाकिस्तान में सैनिक अड्डे तथा काराकोरम राजमार्ग विकसित करके वह इस क्षेत्र में त्वरित हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा चीन को उक्त सामरिक सुविधाएं देने से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वास्तविक अर्थो में अमेरिका के बजाय चीन-पाक में दोस्ती गहरी है। पाकिस्तान और चीन की हिमाचली क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक गतिविधियाँ भारतीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।[4]

भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध और चीन की रणनीति

भारत और अफगानिस्तान दोनों ही देश एशिया के महत्त्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत-पाक बंटवारे से पहले दोनों के मध्य आर्थिक तथा सामरिक सम्बन्ध अत्यधिक मजबूत थे। भारत का अपने प्रति प्राचीन सम्बन्धों के कारण अफगानिस्तान में कई महत्वपूर्ण हित है तथा भारत को अपनी एक मजबूत उपस्थिति अपने हितों की रक्षा के लिए सिद्ध करनी होगी क्योंकि वर्तमान समय में चीन तथा अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियाँ हस्तक्षेप कर रही है।

यद्यपि अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सरकारों व आतंकवादी समूहों के मध्य स्थापित गहरे सम्बन्ध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से चीन की सामरिक घेरेबंदी को ऊर्जा मिल रही है तथा चीन यह कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा

Principal
Dayanand College
HISAR

संचालित आतंकवाद विरोधी अभियान असफल हो क्योंकि इससे अन्ततः इस सम्पूर्ण क्षेत्र में उग्रवाद हेतु अभिप्रेरित करने के अतिरिक्त वहाँ सम्भाव्य राजनैतिक स्थिरता के समक्ष संकट उत्पन्न करेगा।[5]

अफगानिस्तान एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

विकास के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहाँ की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अमेरिकी सेना यदि अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहाँ तालिबानों का प्रभुत्व कायम हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत को अपने द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की भी चिंता होना स्वाभाविक है।

ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान की सेना कमजोर पड़ती है और तालिबान प्रभावी हो जाता है तो अफगानिस्तान में भारत की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तब बड़ा सवाल यह उठेगा कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत को अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है और तब क्या भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजना मुनासिब रहेगा? क्या भारत चाहेगा कि एक देश में जहाँ वह विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर ज्यादा लोकप्रिय बन चुका है, वहाँ अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान की अवाम के बीच किसी आशंका को जन्म दे? यही अफगानिस्तान के साथ सम्बन्धों को लेकर भारत के लिए चिंता का कारण है।[6]

भारत-नेपाल सम्बन्ध और चीन की रणनीति

भारत-नेपाल के मधुर सम्बन्धों के बीच चीन ने अपनी रणनीतिक गतिविधियाँ शुरु कर दी है। तभी चीन सहायता के नाम पर नेपाल को अपने 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति' के एक 'चमकते हुए रत्न' के रूप में स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीन ने नेपाल के प्रति नरम कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर यहाँ अपने प्रभाव वृद्धि हेतु दस चीनी अध्ययन केन्द्र - वुटवल, बानेया, सुखवासभा, पोखरा, विराटनगर, मारांग, सनसारी, चितवन, नेपालगंज व लम्बनी में स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त 'नेपाल चीन सहयोग सोसायटी' की भी स्थापना नेपाल स्थित चीनी दूतावास की आर्थिक सहायता से की गई है जो भारत-विरोधी रणनीतिक गतिविधियों में संलिप्त है।[7]

नेपाल एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

यद्यपि की परिस्थितियाँ बदल गई है और नेपाल में लोकतन्त्र राजतन्त्र पर हावी हो चुका है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा समस्याओं को लेकर नेपाल की ओर से एकदम निश्चिंत हो जाए। नेपाल में भी सारी चीजें अब भी वैसी है, जो निरंकुश राजतन्त्र के जमाने में हुआ करती थी। अतः भारत को इन नयी परिस्थितियों में भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से चौकन्ना रहना होगा।

क्योंकि ब्रिटिश भारत के समय में भी नेपाली शासकों ने चीनी पत्रों का उपयोग किया था। चीन का मतभेद जैसे-जैसे भारत से बढ़ता गया तथा चीन नेपाल के निकट आता गया। चीन ने 1963 में कोडारी-काठमांडू मार्ग बनाना शुरू किया, जो 1965 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के बाद भारत ने अपनी नेपाल नीति की समीक्षा की। युद्ध से यह भ्रान्ति समाप्त हो गयी कि हिमालय को कोई पार नहीं कर सकता है। वर्ष 1965 में भारत ने नेपाल की पंचायत व्यवस्था को मानते हुए हथियारों के सन्दर्भ में समझौता किया। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि भारत नेपाल की रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो अमेरिका और ब्रिटेन उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब भारत की नेपाल से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा चिंता बढ़ गयी है, क्योंकि नेपाल का झुकाव भारत की बजाय चीन की ओर आकर्षित है।

Principal
Dayanand College
HISAR

भारत-भूटान सम्बन्ध और चीन की रणनीति

भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह भारत तथा चीन के बीच अवरोधक राष्ट्र की भूमिका भी निभाता है। भूटान के पश्चिम में स्थित भारत का सिक्किम प्रान्त बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है। भूटान के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी सीमा पर तिब्बत और इसके पूर्व तथा दक्षिण में भारत का असम राज्य है। शुरुआत में भूटान भारत व तिब्बत के बीच में मधुर सम्बन्ध हुआ करते थे। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया तथा तिब्बत के राजा दलाई लामा पर घोर अत्याचार किए। अन्त में दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी। जिसके कारण भारत व चीन के सम्बन्धों में कड़वाहट प्रारम्भ हो गई। आज भारत और चीन के बीच किसी टकराव से इंकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान समय में भी भारतीय सेनाओं के समक्ष चुनौतियाँ काफी बढ़ रही हैं और उसी हिसाब से उनकी जरूरतें भी। ऐसे में भारत को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। इस सजगता की आवश्यकता तब तक बनी रहेगा जब तक दक्षिण एशिया में भारत के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पड़ोसी देशों, चीन व पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होती अथवा इनके साथ भारत के सम्बन्ध मधुर नहीं बनते। चीन भारत को अपना प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मानता है, इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तथा श्रीलंका में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर भारत की घेराबंदी करने में लगा है। चीन के विस्तारवादी चरित्र के कारण ही भूटान के डोकलाम में भारत और चीन के बीच टकराव की समस्या पैदा हो गई थी। भारतीय सेना ने भूटान के डोकलाम में 16 जून, 2017 को चीन के सड़क निर्माण के प्रयास को रोक दिया। इसी समय दोनों सेनाओं के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया था। यदि चीन सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है तो चीन की पहुँच भारत के पूर्वोत्तर इलाके तक हो जाती। जो कि भारत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय था।[9]

भूटान एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद भूटान भी चीन से भयभीत हो गया। चीन द्वारा 1953 में प्रकाशित कई मानचित्रों में उत्तर पूर्वी भूटान का बड़ा भाग तिब्बत के अंश के रूप में दिखाया गया। चीन द्वारा भूटान पर सीमा निर्धारण के प्रश्न पर सीधी बातचीत हेतु दबाव दिया जाता रहा है। जिस पर भूटान ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 1984 से भूटान और चीन के बीच सीमा निर्धारण के प्रश्न पर सीधी वार्ता होती रही है परन्तु सार्थक हल नहीं निकल सका। चीन की रणनीति आक्रामक कूटनीति के बजाय शान्ति आक्रमण के जरिए भूटान को जीतने की है।[10]

भूटान हमारा एक उत्तर पूर्वी छोटा पड़ोसी राष्ट्र है जिससे हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मधुर हैं। भूटान भारतीय सुरक्षा नीतियों का अनुसरण करता है। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा चिन्ताओं का प्रश्न है हमारी तथा भूटान की चिन्ताएँ एक सी है।[11]

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध और चीन की रणनीति

भारत-पाक बंटवारे से पूर्व बांग्लादेश भारत का ही एक अंग था। बंटवारे के पश्चात् भी बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल कहा गया, जबकि ठीक इसी तरह एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उससे बिल्कुल सटा हुआ अवस्थित है। अत: भारत-बांग्लादेश की पारस्परिक निर्भरता में ऐतिहासिक कारक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए स्वतन्त्रता के बाद बांग्लादेश सरकार के नेताओं द्वारा शेख मुजीब से लेकर जियाउर्रहमान तक भारत के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने पर बल दिया। लेकिन भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों में यह विड़म्बना रही है कि दोनों देशों के सम्बन्ध विवादों तथा मुद्दों को लेकर कटु (कड़वे) होते गए।

जिसका फायदा उठाकर पाक-चीन जैसी विदेशी ताकतों का उस पर प्रभाव बढ़ता गया। क्योंकि शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेशी सरकार दोहरी रणनीति पर कार्य कर रही है। एक ओर वह भारत के साथ

Principal
Dayanand College
HISAR

सम्बन्धों को बढ़ाना चाहती है तथा दूसरी ओर चीन से सहयोग प्राप्त कर भारत की घेराबंदी करना चाहती है। इसलिए चीन बांग्लादेश केचटगाँव बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है।

बांग्लादेश एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख बांग्लादेश की चुनौती को सामरिक विशेषज्ञ भविष्य के बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। बांग्लादेश में भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अलगाववाद को हवा दे रही आई.एस.आई. उल्फा व चीनी हथियारों व सक्रियता का ऐसा गठजोड़ बन गया जो भारत की पूर्व सुरक्षा हेतु घातक है।

भारत में लगभग सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों (विशेषतया सीमावर्ती) में बांग्लादेशी घुसपैठियों की खासी आबादी है। और वे आतंकवादियों के लिए ''स्लीपर-सेल'' का कार्य करती है। आई.एस.आई. प्रेरित आतंकवादी अब बांग्लादेश का उपयोग ''लांचिंग पैड'' के रूप में करने लगे हैं। करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों के यहाँ रहने व निरन्तर घुसपैठ जारी रहने को बांग्लादेश से मूक समर्थन मिलना भारतीय सुरक्षा के सम्मुख विकराल चुनाती है।[13]

भारत-मालदीव सम्बन्ध और चीन की रणनीति

मालदीव दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश होते हुए भी एशिया समुदाय का एक सक्रिय सदस्य है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर भारत और मालदीव के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ और मधुर रह है। भारत ने मालदीव के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मालदीव क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला एक विश्वसनीय मित्र है। लेकिन चीन का मालदीव में बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ने मालदीव में भारत को अपने कूटनीतिक चाल से मात दी है।''[14]

मालदीव एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

हिन्द महासागर के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों के मार्ग पर स्थित होने के कारण विश्व की कई शक्तियाँ मालदीव की भू-स्त्रातेजिक अवस्थिति का लाभ उठाने हेतु प्रयत्नशील हैं। इस क्षेत्र की बदल रही भू-राजनतिक स्थिति के फलस्वरूप चीन भी मालदीव में नौ सैन्य आधार विकसित करने हेतु प्रयत्नशील है। जिससे हिन्द महासागर क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के साथ-साथ वैश्विक आतंकवाद के प्रसार को नई ऊर्जा दी जा सके। मालदीव में चल रही उक्त गतिविधियाँ भारतीय सुरक्षा के लिए ऐसी ज्वलन्त चुनौतियाँ है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।[15]

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध और चीन की रणनीति

श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, जो भारतीय समुंद्र से घिरा है। इस तरह श्रीलंका की स्थिति भारत के दशष्टिकोण से काफी मायने रखती है। पारस्परिक रूप से भारत का इससे अच्छा सम्बन्ध रहा है। परन्तु वर्तमान समय में चीन की रणनीति ने भारत श्रीलंका सम्बन्धों में खटास प्रारम्भ कर दी है। जिसका प्रमुख कारण दक्षिण एशिया में अपने व्यापारिक व रणनीतिक हितों की पूर्ति हेतु 'ग्वादर' व 'चटगाँव' के बाद श्रीलंका के 'हम्बनटोटा बन्दरगाह' के निर्माण एवं वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएँ विकसित करने हेतु चीन युद्धस्तर पर सक्रिय है। इस परियोजना के समग्र विकास हेतु चीन लगभग 1.4 बिलियन की सहायता श्रीलंका को दे चुका है।

यद्यपि श्रीलंका में चीन की निरन्तर बढ़ रही सामरिक अभिरूचि भारतीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है तथापि श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने स्पष्ट कहा कि - ''चीन के साथ उनके सुधर रहे सम्बन्ध भारत के लिए कदापि प्रतिकूल नहीं है।''[16]

इसलिए भारत श्रीलंका को अपने सम्बन्ध मजबूत करने होंगे अन्यथा यहाँ बाह्य शक्तियों की बढ़ती जा रही सामरिक गतिविधियाँ भारतीय सुरक्षा के समक्ष गम्भीर चुनौती सिद्ध होगी।[17]

Principal
Dayanand College
HISAR

श्रीलंका एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

श्रीलंका हमारी दक्षिणी पड़ोसी राष्ट्र है। वहाँ के सिंहली व तमिल दोनों ही भारतीय श्रीलंका मूल है। सिंहली यहाँ से पहले गए और तमिल बाद में। चूंकि सिंहली जनसंख्या अधिक है इसलिए वहाँ की शासन व्यवस्था में उसका प्रभुत्व है। वहाँ लम्बे समय तक सिंहली-तमिल विवादों तथा जातीय संघर्षो से उभरा अलगाववाद व आतंकवाद वहाँ की आन्तरिक समस्या है। ऐसा मान कर ही भारत वहाँ शान्ति स्थापना में सहयोग दिया है। लिट्टे का नटवर्क धराशायी होने व प्रभाकरण के मारे जाने के बाद वहाँ शान्ति स्थापना की आशा की जा सकती है। श्रीलंका की ओर से फिलहाल भारत के सम्मुख सुरक्षा चुनौतियाँ लगभग नगण्य है।[18]

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र आपस में जुड़े हुए है फिर भी यहाँ क्षेत्रीय एकीकरण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र एक लम्बे समय से विभिन्न प्रकार के संघर्षो तथा विवादों से ग्रसित है। भारत ने दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सदैव मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया है, लेकिन विड़म्बना यह है कि उसे सदैव इन राष्ट्रों से चुनौती मिलती रही है।

वर्तमान वस्तुस्थिति यह है कि दक्षिण एशिया के इन राष्ट्रों में घरेलू मोर्चे एवं आपसी टकराव की कई परिस्थितियाँ बनी हुई है। जिसका फायदा उठाकर अमेरिका तथा चीन जैसी बड़ी विश्व शक्तियों ने दक्षिण एशियाई भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अपनी प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है। चीन अपनी रणनीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक तथा सैनिक सहायता देकर भारत की दक्षिण एशिया में जल व थल में भारत की घेराबंदी करना चाहता है। इसके लिए चीन दक्षिण एशिया में भारत को घेरने हेतु "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" के जरिए नौ सैनिक अड्डों की स्थापना कर रहा है वे है - ग्वादर (पाकिस्तान), चटगाँव (बांग्लादेश), हम्बनटोटा (श्रीलंका),. हांगई कोको (म्यांमार), मराओ (मालदीव)।

इसके अतिरिक्त चीन-पाक धुरी व पाकिस्तान के काराकोरम राजमार्ग का निर्माण, नेपाल के पथलहिमा से बांग्लादेश की सीमा काकर-मीटठा तक 'फोर लाइन ट्राफिक' पथ का निर्माण, नेपाल तथा बांग्लादेश को आर्थिक तथा सैनिक सहायता, मालदीव माले के एयरपोर्ट निर्माण का ठेका तथा श्रीलंका को Jian&7 फाइटर, JY-II-3D हवाई टोही राडार कवचित वाहन, T-56 एसाल्ट राइफलें, मशीनगन एवं एंटी काफ्टगन जैसे आधुनिकतम शस्त्रों की आपूर्ति इत्यादि।

स्पष्ट है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ चीन के बढ़ रहे सामरिक आर्थिक सम्बन्ध क्षेत्रीय विकास व स्थिरता हेतु महत्त्वपूर्ण तो हो सकते है किंतु उक्त गतिविधियों की आड़ में चीन की महत्त्वाकांक्षाएं भारत की सामरिक घेरेबंदी पर केन्द्रित प्रतीत होती हैं। जो भारत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

संदर्भ-सूची

1. गुलाब चन्द्र ललित, रवीन्द्र प्रताप सिंह, भारत और उसके पड़ोसी, मोहित पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2017 पृ. 211-213
2. आर.एस. यादव, भारत की विदेश नीति, किताब महल, नई दिल्ली, 2005, पृ. 264
3. प्रो. (डॉ.) राम प्रवेश शर्मा, भारतीय विदेश नीति तथा हमारे निकटतम पड़ोसी, 2009, पृ. 152
4. डॉ. आर.एस. पाण्डेय, चीन केन्द्रित भारत की सुरक्षा चिन्ताएं यथार्थ एवं निहितार्थ, आकृति प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. 262-263
5. Rajan Menon, The New Great Game in Central Asia, Survival, Vol. 45 No. 2 (Summer 2003), P. 187
6. https://www.drishtiial.com>hindi

Principal
Dayanand College
HISAR

7. डॉ. आर.एस. पाण्डेय, चीन केन्द्रित भारत की सुरक्षा चिन्ताएं यथार्थ एवं निहितार्थ, आकृति प्रकाशन, 2017, पृ. 33-37
8. कृष्णानन्द शुक्ल, भारत और एशियाई देश, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 54, 85-86
9. डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव, अरिहन्त सामयिकी महासागर, जुलाई, 2011, चीन-पाक से मिलती सामरिक चुनौतियाँ, पृ. 68
10. कृष्णानन्द शुक्ल, भारत और एशियाई देश, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 127-129
11. डॉ. अजय कुमार, डॉ. विपिन कुमार शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा की सामयिक चुनौतियाँ, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 11
12. अजय कुमार सिन्हा, पूर्वोत्तर के आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका, राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक समस्याएँ, नई दिल्ली, पृ. 258
13. दैनिक जागरण, 13 सितम्बर, 2009, पृ. 1
14. Dipanjan Roy Chaudary, Chinese Company bags Maldivian is land on 50 year iease, Economic Times, 30 Dec., 2016
15. डॉ. आर.एस. पाण्डेय, चीन-केन्द्रित भारत की सुरक्षा चिन्ताएँ यथार्थ एवं निहितार्थ, आकृति प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. 54-55
16. Outlook, 7 Feb, 2012
17. Alok Bansal, Demo cratisation of Maldives, A challenging Roadmap cited in S.D. Muni (ed) Asian Strategic Review, 2008 P. 237
18. डॉ. अजय कुमार सिन्हा, डॉ. विपिन कुमार शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा की सामयिक चुनौतियाँ, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 11

Principal
Dayanand College
HISAR